यह कहना तो तथ्यों का उपहास करना है कि भूख हड़ताल गुजरात में चुनाव कुछ महीने पहले कराने की दृष्टि से ही की गई थी। संविधान में प्रदत्त लोगों के अधिकार खतरे में थे। परिसीमन कार्य दिसम्बर, 1974 में ही पूरा हो गया था और निर्वाचन तंत्र भी संगठित कर लिया गया था। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य को इतनी महत्ता नहीं दी गई। अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने बार-बार ये आश्वासन दिये हैं कि मतदाता सूचियां तैयार होने तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा होने के तुरन्त बाद चुनाव-कार्य कराये जायेंगे फिर भी जनवरी-फरवरी में चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया गया, जो कि दिया जाना चाहिये था। परन्तु राष्ट्रपति शासन की अवधि इस संभावना के साथ 6 महीने और बढ़ा दी गई कि यह आगे भी इसी अवधि तक के लिये अथवा दो महीने की अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है। गत मार्च में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से तो इस संबंध में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है।

प्रधान मंत्री इस आधार पर आपात स्थिति हटाने को अनिच्छुक है कि आज की परिस्थितियों में ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी खतरों के उत्पन्न होने पर आपात स्थिति पुनः लागू की जा सकती है। अतः अब और अधिक समय तक आपात स्थिति जारी रखने में कोई औचित्य नहीं है।

समाज विरोधी तत्वों तथा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये सरकार को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम से अधिक शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये लेकिन इस शक्ति को राजनतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। यह संतोष का विषय है कि प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम का उद्देश्य वैध राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाना नहीं है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस अधिनियम के पालन न करने के बारे में की गई शिकायतों की जांच करेंगे।

मैं माननीय संसद सदस्यों, अन्य देशवासियों और नेताओं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनशन के दौरान मेरे साथ सहानुभूति और एकता प्रदर्शित की है।

प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के संबन्ध में वक्तव्य
STATEMENT RE. SUCCESSFUL LAUNCHING OF FIRST INDIAN SATELLITE

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सभा को 19 अप्रैल, 1975 के 1 बजे मध्यान्ह पश्चात प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बारे में पता है। उपग्रह पूर्णतः भारत में ही तैयार किया गया और सोवियत राकेट कैरियर की सहायता से सोवियत संघ से छोड़ा गया है।

विकासशील देश की यह पहली महान उपलब्धि राष्ट्रीय विकास के लिये आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त करने के हमारे प्रयत्नों की एक और महान सफलता है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के अतिरिक्त बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने में विशेष योगदान कर सकती है।

उपग्रह और इसके प्रेक्षपण तथा रख-रखाव के लिये आवश्यक सम्पूर्ण स्थल व्यवस्था तीन वर्ष से कम अवधि के भीतर तैयार कर ली गई थी। मैं प्रो० सतीश धवन के नेतृत्व में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्य करने वाले निष्ठावान और कर्त्तव्यनिष्ठ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा इस कार्य में

लगे अन्य सहयोगियों के इस महान् कार्य के लिए अपनी और सरकार की सराहना रिकार्ड में रखना चाहती हूं। मैं इस कार्य में सोवियत संघ द्वारा दी गई सहायता तथा प्रक्षेपण सुविधाओं के लिये सोवियत संघ को भी अपना आभार व्यक्त करती हूं।

अनुदानों की मांगे ,1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—Contd.

वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा।

श्री पीलू मोदी : इससे पहले कि आप अगले मद को लें, मेरा एक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूं जब तक आप बैठ नहीं जायेंगे। अब सभा में वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 11 और 12 पर चर्चा और मतदान होगा।

वाणिज्य मंत्रालय को वर्ष 1975-76 की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	राजस्व	पूंजी
	रु०	रु०
11. वाणिज्य मंत्रालय . .	14,64,000	—
12. विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन	33,28,62,000	47,79,38,000

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था और समृद्धि व्यापार और वाणिज्य कार्य द्वारा आंकी जा सकती है।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the Chair]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 वर्ष बाद भी भारत सरकार ने देश में व्यापार-सन्तुलन बनाये रखने में विश्व को मुख्य घटनाओं से कोई पाठ नहीं सीखा है।

इसके बावजूद सरकारी प्रवक्ताओं ने निर्यात व्यापार में भारी सफलता प्राप्त करने के लम्बे लम्बे दावे किये हैं। उन्होंने निर्यात-आय में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में भी भारी प्रचार किया है। हमें इस प्रचार के खोखलेपन की जांच करनी चाहिये।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1973-74 में भारत की निर्यात-आय कुल 2483 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह 1972-73 के निर्यात-आय की तुलना में 512 करोड़ रुपये या 26 प्रतिशत अधिक है। निर्यात-संवर्धन के आंकड़े उस गंभीर संकट को दबाते हैं जिसमें हमारा विदेश व्यापार गिरा है।